में कर रही है जिससे पोलिस्टर ज्यादा से ज्यादा यूज होगा काटन में, उससे काटन की जो खपत है वह और कम होगी।

MR. SPEAKER: Let not the hon. Member make a speech before he puts his question. Please come to the question.

डा० बलदेव प्रकाश : और आज ही एक रिजोल्यूशन आ रहा है कि सरकार काटन की ऐक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है। तो इन सारी चीजों से काटन की कीमत और डाउन जायेंगी। तो सरकार कौन से कदम उठा रही है कि जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं काटन की उनकी कीमत कम आये और फार्मर्स को ज्यादा कीमत मिले ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, यह दाम नीति का सवाल है, और मैं मानता हूं कि इस पर कुछ कदम उठाने बहुत जरूरी हैं जिसके चलते रा-मैटीरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के दाम में तालमेल हो जाय। मगर कुल दाम नीति बना कर ही यह काम हल हो पायेगा। किसी भी क्षेत्र के बारे में मैं नहीं समझता इसको अमल में लाना सम्भव होगा।

PROF. R. K. AMIN: Sir, what I feel is that there is a problem of different prices in different States prevailing for cotton. That is the reason. That is because of the inconsistency of the Government policy. In Maharashtra, we purchase cotton even well above the support price. In Gujarat and Punjab, they do not purchase cotton at the support price or even below the support price when the farmers are ready to give them. They say that even the credit policy.....

MR. SPEAKER: Let there be no debate. Please come to the question.

PROF. R. K. AMIN: Why, in spite of having an integrated policy regarding the purchase of cotton, this has not been implemented. Will the Minister assure us that steps will be taken to have an integrated policy regarding the cotton purchases all over the country?

SHRI GEORGE FERNANDES: We are currently discussing this matter. As soon as I work out a new policy, I shall come to the House.

वर्ष 1978 के दौरान स्थापित किये गये लघु उद्योगों की संख्या

*128. श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 के दौरान कितने लघु उद्योग स्थापित किये गये ;

(ख) ऐसे कितने उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव था ; और

(ग) यदि योजना के अनुसार उद्योगों की स्थापना नहीं की गयी तो उसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) According to the information received so far, 17314 units have been set up and registered in the different States in 1978. Information for several districts and some quarters of the year in respect of districts which have furnished the information are still awaited.

(b) The small scale is a sector where an entrepreneur can set up a unit in any line with or without assistance from the Government. The Government only provides advice, assistance and incentives for the setting up of small scale units. As such it is difficult to set any targets for the number of units to be set up.

(c) Does not arise.

श्री हरगोविन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत की गरीबी और बेकारी दोनों से सम्बन्ध लघु उद्योग रखते हैं अगर देश में लघु उद्योग लग जायें तो बेकारी और गरीबी दूर हो। इस बात के समर्थक और हमदर्द मंत्री जी भी हैं और माननीय चौधरी साहब भी कई बार यह बात कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी लघु उद्योग हमारी जानकारी में किसी भी जिले में प्रदेश में नहीं लगे हैं। क्या मंत्री जी इसके लिये कोई विशेष योजना बना रहे हैं और बना कर के उसको लागू करने की योजना करेंगे और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करेंगे इसका कारण बतायेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि हम लोग इस मामले में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिला औद्योगिक केन्द्र 242 जिलों में अभी तक बने हैं। यह साल पूरा होने तक। अगले 6 महीनों में दरअसल 400 जिलों में भी जिला औद्योगिक केन्द्र के निर्माण करने का काम हो जायेगा, और कुल अगले 5 साल में छोटे उद्योगों के विकास की जो योजना बनायी गई हैं उसमें हम यह उम्मीद रख रहे हैं कि लगभग साढ़े 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो जायगी उसमें कुल लगभग 40 लाख लोगों को अगले 5 सालों में हम अधिक काम में लगा पायेंगे। तो इस दिशा में हम ठोस कदम उठा रहे हैं, और सारा जो भार हम दे रहे हैं इस समय वह छोटे उद्योगों के निर्माण पर ही है।

श्री हरगोविन्द वर्मा : मंत्री जी ने जैसा बताया है, उस तरीके से 2 साल बीत गये हैं लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। राज्य सरकारों ने निश्चित रूप से अन्त्योदय के माध्यम से गरीबों के लिये योजना बनाई है लेकिन वह सफल होती नजर नहीं आ रही है। अधिकारियों के द्वारा गरीबों को जो 5,5 हजार रुपया दिया जा रहा है, वह भी मिल नहीं पा रहा है, यदि मिलेगा भी तो आधा बिचवनिया खा जायेंगे। अगर सरकार ने इस तरह की योजना बनाई कि 5,5 हजार रुपये एक परिवार में लगाये और 5 परिवारों को एक गांव सभा में रुपया दे तो इस तरह से 25 हजार रुपया होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार 50 हजार या 1 लाख रुपये एक गांव में लगाकर एक यूनिट खड़ा करेगी जिसमें गरीबों और बेकारों को रोजगार मिल सके? क्या ऐसा करने को सरकार तैयार है?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : तमाम छोटे उद्योगों के विकास का काम राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। केन्द्रीय सरकार के जरिये इस उद्योग को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक केन्द्रों की योजना बनाई गई है। उसको बढ़ाने के लिये और कानूनी दिक्कतों को दूर करने के लिये हमने कई कदम उठाये हैं और राज्य सरकारों के माध्यम से इसका अमल हम कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य की इस राय से सहमत नहीं हूं कि इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा है। मैंने बताया कि जो जानकारी हमारे पास आई है, उसके आधार पर भी पिछले साल 17 हजार से अधिक छोटे उद्योगों को लगाने का काम देश में हुआ है। हालांकि हमारी जानकारी के अनुसार उसमें भी काफी अधिक इस प्रकार के छोटे उद्योगों को उन्होंने लगाया है।

SHRI VIJAYKUMAR N. PATIL: The Central Government gave seed capital to the tune of 15 per cent in some of the districts of various States. Like that in Maharashtra three districts, viz., Aurangabad, Ratnagiri and Chandrapura were covered. But I am given to understand that this scheme is being dropped by the government. If so, what will happen to the new proposal which are coming up in those backward areas and the infra-structure built there?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, government is not dropping the scheme. What has happened is that in the last meeting of National Development Council it were the States who insisted on having the seed money being made part in the State governments allocation without being earmarked as such. However, this matter is still being taken up with the Planning Commission to see whether it is possible to continue with this scheme.

डा. रामजी सिंह : उद्योगों के विकास के लिये जो प्रयत्न हो रहा है, वह बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सैंटर्स कायम किये गये हैं, इसके माध्यम से पिछले 8 महीनों में सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में कितने नये उद्योग लगे हैं और उसमें कितने लोगों को अभी तक रोजगार मिल सका है?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नई नीति के चलते जिला औद्योगिक केन्द्रों का पिछले अगस्त महीने से ही काम शुरु हुआ है और अभी तक हमारे पास कुल मिलाकर 100 जिला औद्योगिक केन्द्रों से जानकारी आनी शुरु हुई है। इस बारे में विस्तार में जानकारी देने के लिए हमको नोटिस चाहिये।

Sale of Coca-Cola at Rs. 2/- per Bottle

*129. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have inquired into the availability of Coca-Cola in Delhi market and elsewhere at Rs. 2/- per bottle which is a banned drink;

(b) if so, what action has been taken against the manufacturer of this spurious drink; and

(c) whether any case has come to the notice of Government about manufacture of this drink by any established Company?